

**न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली**

पीठासीन अधिकारी : डॉ० भास्कर विश्वा, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 106/2025 G.C.M.S. No. 2025/583 दर्ज दिनांक : 28.08.2025  
अपीलाधी:

1. हरिसिंह पुत्र सूरतसिंह, जाति रावत, निवासी रोडावास, तहसील सोजत, जिला पाली।

**बनाम**

प्रत्यर्धिगण:

1. कंवरीबाई पत्नि विरदसिंह
2. विरदसिंह पुत्र जगेशिंह, जातिगण रावत, तहसील सोजत, जिला पाली।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत सिटी, जिला पाली।



अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 167/2022 बअनवान कंवरीबाई वगैरह बनाम हरिसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 02.06.2025 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार-

1. श्री श्रवणसिंह चौहान, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री गजेन्द्र दवे, श्री सुनील दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

**निर्णय**

दिनांक: 30.01.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 167/2022 बअनवान कंवरीबाई वगैरह बनाम हरिसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 02.06.2025 के विरुद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है-

यह कि हस्तगत प्रकरण में रेस्पोंडेंट संख्या 01 व 02 द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय में धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रोडावास मे अपनी जोत में पहुँचने के लिए अपनी खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 842, रकबा 0.4200 हैक्टेयर, किस्म बॉरानी दोयम सरहद मौजा ग्राम रोडावास पटवार क्षेत्र गुडाकला भू: अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र गुडा कला तहसील की जोत मे जाने हेतु नया मार्ग अप्रार्थी संख्या 01 व 02 यानि अपीलाण्ट व रेस्पोंडेंट संख्या 03 की खातेदारी खसरा संख्या 843, रकबा 0.1500 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 843/1 हैक्टेयर रकबा 1.000 हैक्टेयर में से अपनी खातेदारी भूमि मे जाने हेतु आशय रखे हुए प्रस्तुत किया जिस पर उक्त प्रकरण दिनांक 31/10/2022 को दर्ज होकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलाण्ट को नोटिस प्राप्त होने पर

दिनांक 22/04/2025 को अपीलान्त की ओर से अधिवक्ता कुन्दनसिंह सांजू को नियुक्त किया तथा अधिवक्ता कुन्दनसिंह सांजू द्वारा दिनांक 22/04/2025 को अप्पर टैकिंग की परन्तु अधिवक्ता कुन्दनसिंह द्वारा दिनांक 20/06/2025 को उपस्थित नहीं हुए और न ही अपीलान्त की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया जिससे दिनांक 20/06/2025 को माननीय अधिनरथ न्यायालय द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर दिनांक 02/06/2025 को खसरा नम्बर 843 व अपीलान्त के खसरा 843/1 में से रास्ता दिये जाने हेतु बाबत आदेश पारित किया गया। अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत करने व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा अपीलान्त के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर जैर अपीलान्त निर्णय पारित किया गया है।

रेस्पोजेण्ट संख्या 01 व 02 का पूर्व से आवागमन सरकारी भूमि में से होकर निरंतर चला आ रहा है और रेस्पोजेण्ट संख्या 01 व 02 द्वारा उसका कदिमी से उपयोग उपभोग किया जा रहा है इस कारण नये रास्ते की कानुनन मांग नहीं कर सकते। मौके की स्थिति की रिपोर्ट सही रूप से तैयार नहीं की गयी जबकि खसरा नम्बर 842 व 843 के पास स्थित खसरा संख्या 929 में रेस्पोजेण्ट संख्या 01 व 02 का मकान है जिससे सीधा रास्ता रेस्पोजेण्ट संख्या 01 व 02 के खेत खसरा नम्बर 842 में जाता है व रेस्पोजेण्ट संख्या 01 व 02 के मकान से सीधा आम रास्ते में जाता है। मात्र खानापूर्ति कर खसरा नम्बर 843 की भूमि को हडपने व अपीलान्त की भूमि से रास्ता दिये जाने की नियत से तैयार की गयी है। मौका रिपोर्ट विधि अनुसार तैयार नहीं की गयी है एवं नियम 18 व 21 की पालना नहीं की गयी है और न ही मौका रिपोर्ट अपीलान्त की उपस्थिति में तैयार की गयी है और न ही रेस्पोजेण्ट संख्या 01 व 02 के घर से खसरा नम्बर 842 के जाने के रास्ते व उक्त रास्ते के आगे रेस्पोजेण्ट संख्या 01 व 02 के घर से सीधे आम रास्ते में जाने वाले तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है मात्र खानापूर्ति कर मौका रिपोर्ट तैयार की गयी है एवं विधि विरुद्ध तरीके से तैयार की गयी है मौका रिपोर्ट के आधार पर जैर अपीलान्त निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्त की जोत खसरा नम्बर 843/1 भूमि 1.0000 हैक्टेयर है। अपीलान्त की जोत में से रास्ता दिया जाता है तो अपीलान्त की भूमि कम हो जायेगी। अपीलान्त की रोजी रोटी का जरिये उक्त कृषि भूमि ही है तथा अपीलान्त की कृषि भूमि से रास्ता दिये जाने से उक्त कृषि भूमि, कृषि भूमि योग्य नहीं रहेगी। प्रार्थी को उक्त निर्णय के बारे में कोई जानकारी नहीं थी तथा प्रार्थी के बीमार होने के कारण अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सका तथा दिनांक 17/08/2025 को अनजान व्यक्ति प्रार्थी के घर आया और प्रार्थी से कहा की आपके खेत के मुआवजे क चौक आया है। इस कारण हस्ताक्षर करो परन्तु प्रार्थी ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया तब उस व्यक्ति ने कहा की मैं कोर्ट से आया हूँ और फोन पर किसी अन्य व्यक्ति से बात करवाई



राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय  
काठवाड़ जिला

जिसने कहा की आपके विरुद्ध आदेश पारित हुआ है। आप चौक ले लो फिर आप चाहे तो अपील करना। तब प्रार्थी को आश्चर्य हुआ और प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता कुन्दनसिंह सांदू को फोन किया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया तथा प्रार्थी ने उस व्यक्ति को कहा कि वह कल सोजत जाकर अपने अधिवक्ता से बात करेगा फिर प्रार्थी दिनांक 18/08/2025 को सोजत आकर तथा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने की कोशिश की परन्तु प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थी का कॉल रिसिव नहीं किया तो प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में गया और नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर प्रार्थी को दिनांक 19/08/2025 को उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई तथा दिनांक 21/08/2025 को प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मय निर्णय की प्रमाणित प्रति मिली। जिससे उक्त प्रकरण की पत्रावली को देखने पर प्रार्थी को जानकारी हुई। तत्पश्चात उक्त अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमायें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांत दर्ज रजिस्टर की

जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमने प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उमयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन

निम्नानुसार है-

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोंडेंट्स द्वारा अपनी खातेदारी आराजी ग्राम रोड़ावास तहसील सोजत के खसरा संख्या 842 की आराजी तक पहुंच के लिए खसरा संख्या 843, 843/1 में से रास्ता स्वीकृत करने हेतु अपीलांत के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 02.06.2025 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरुद्ध अपीलांत द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 28.08.2025 को विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।

2. अपीलांत द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया है कि प्रार्थी को उक्त निर्णय के बारे में कोई जानकारी नहीं थी तथा प्रार्थी के बीमार होने के कारण अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सका तथा दिनांक 17/08/2025 को अनजान व्यक्ति प्रार्थी के घर आया और प्रार्थी से कहा की आपके खेत के मुआवजे क चौक आया है। इस कारण हस्ताक्षर करो परन्तु प्रार्थी ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया तब उस व्यक्ति ने कहा की मैं कोर्ट से आया हूँ और फोन पर किसी अन्य व्यक्ति से बात करवाई जिसने कह की आपके विरुद्ध आदेश पारित हुआ है। आप चौक ले लो फिर आप चाहे तो अपील करना। तब प्रार्थी को

आश्चर्य हुआ और प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता कुन्दनसिंह सांदू को फोन किया लेकिन उन्होंने


अधीनस्थ न्यायालय  
पत्रावली

कोन नहीं उठाया तथा प्रार्थी ने उस जति को कहा कि वह काज लोकार जाकर अपने अधिवक्ता से बात करेगा फिर प्रार्थी दिनांक 18/08/2025 को लोकल प्रकरण तथा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने की कोशिश की परन्तु प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थी का जति सिरिब नहीं किया तो प्रार्थी अधिवक्ता न्यायालय में गया और नकल प्रार्थन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर प्रार्थी को दिनांक 19/08/2025 को उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई तथा दिनांक 21/08/2025 को प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मय निर्णय की प्रमाणित प्रति मिली। जिससे उक्त प्रकरण की पत्रावली को देखने पर प्रार्थी को जानकारी हुई। अतः अपील अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. हमारे विनम्र मत में प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं है तथा अपीलधीन आदेश अपीलांट की गैर मौजूदगी में पारित किया गया है तथा प्रकरण में गुणावगुण से संबंधित सारवान प्रश्न विद्यमान है तथा विलंब अपीलांट की लापरवाही से होना साबित नहीं है। अतः विलंबकाल सद्माविक व युक्तियुक्त होने से माफ किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।



4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में भू.अ.नि. गुडा कलां द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व समय व दिनांक का निर्धारण नहीं किया गया तथा न ही पक्षकारान को मौके पर उपस्थिति हेतु सूचित किया गया। मौका रिपोर्ट के पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक व दिनांक के कॉलम रिक्त होने से इसकी पुष्टि होती है। अतः स्पष्ट है कि प्रकरण में भू.अ.नि. द्वारा पक्षकारान की गैर मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की गई। भू.अ.नि. द्वारा मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा में प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता प्रस्तावित किया गया। जबकि भू.अ.नि. द्वारा प्रार्थी की आराजी तक पहुंच के लिए सभी संभव विकल्प प्रस्तावित किए जाने अपेक्षित थें ताकि न्यायालय द्वारा निकटतम दूरी के विकल्प का निर्धारण किया जाकर विधिसम्मत आदेश पारित किया जाता। लेकिन मौका रिपोर्ट में उक्त का अभाव पाया गया। इसी प्रकार मौका रिपोर्ट में अंकित सी से डी मौके पर चलायमान रास्ता अंकित किया गया है। जो आगे खसरा संख्या 757 गैर मुमकिन सेरिया से मिलता है। ग्राम गुडाकलां के भू-नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 842 सहित खसरा संख्या 843 व 843/1 की दक्षिण सीमा के सहारे खसरा संख्या 929 गैर मुमकिन गोचर भूमि हैं तथा प्रस्तावित मौके पर चलायमान रास्ता सी से डी खसरा संख्या 843/1 की पूर्वी सीमा से लगती हुई खसरा संख्या 929 गैर मुमकिन गोचर में से चलायमान है। अतः स्पष्ट है कि प्रार्थी उक्त गोचर भूमि में से अपनी आराजी खसरा संख्या 842 तक आवागमन कर सकता है। लेकिन संबंधित भू.अ.नि. द्वारा उक्त समस्त तथ्यों की जांच किए बिना अपूर्ण जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस पर

  
राजस्थान अपील प्राधिकरण  
जापुर

गौर किए बिना उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलधीन आदेश पारित किया गया। जो पुष्टि योग्य नहीं है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांत बखूबी साबित होने से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विधिनुरूप पुनः निर्णयन के लिए प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

### आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांत अंतर्गत धारा 225 राजस्थान कायतकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 167/2022 बजनवान कंवरीबाई वगैरह बनाम हरिसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 02.06.2025 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांत को जवाब प्रस्तुत करने के अधिकतम 2 अवसर प्रदान करते हुए, प्रकरण में धारा 251-क एवं नियम 69 में विहित प्रावधानों तथा इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना करते हुए तथा प्रार्थी की आराजी तक पहुंच के लिए सभी संभव विकल्प प्रस्तावित करवाते हुए पुनः विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण 60 दिवस में विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 27.02.2026 को असालतन/वकालतन अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी सोजत में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(डॉ० भास्कर बिश्नोई)

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

